शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी, 31 मार्च 2021 तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे

प्रदेश में 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा नवीन शैक्षणिक सत्र, सीएम ने की समीक्षा

विशेष संवाददाता, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड के चलते प्रदेश में कक्षा 01 से 08 तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। आगामी शैक्षणिक सत्र 01 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा। कक्षा 01 से 08 तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी तथा इनकी कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होंगी। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य

सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा। कक्षा 09 एवं 11 के विद्यार्थियों को सप्ताह में 01 या 02 दिन स्कूल बुलवाया जाएगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव मनोज गोविल आदि उपस्थित थे। चौहान ने कहा कि ■ शेष पृष्ठ 9 पर

सरकार का दोहरा मापदंडः अफसरों को दिया पूरा वेतन कर्मचारियों का 30 फीसदी काटकर बचाया 500 करोड़

भास्कर न्यूज | भोपाल

राज्य सरकार ने 2020 फरवरी के बाद भर्ती हुए 5000 कर्मचारियों की 30 फीसदी सेलरी कट कर 500 करोड़ रुपए की बचत की है, जबकि इस दरम्यान यूपीएससी और पीएससी से भर्ती हुए अफसरों को शत प्रतिशत वेतन दिया। इस तरह प्रदेश में पहली बार अफसरों और कर्मचारियों की भर्ती के बाद वेतन निर्धारण में यह दोहरे मापदंड सामने आए हैं।

इस साल प्रदेश में सीधी भर्ती और अनुकंपा से भर्ती हुए 5000 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन से फरवरी से नवंबर के बीच 500 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। वहीं, अखिल भारतीय सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों की नई भर्तियों के मामले में प्रोबेशनरी पीरिएड में भी 100 फीसदी भुगतान किया गया। नए कर्मचारियों के मामले में अगले दो साल में इसी तरह सेलरी कट कर 1000 करोड़ रुपए बचाए जाने की योजना है। सरकार के इस फैसले से नई भर्ती से आए कर्मचारियों में नाराजगी है। इस मामले में सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग के अफसरों का कहना है कि यह सरकार का फैसला है।

दरअसल, सरकार ने एक आदेश जारी कर नान पीएससी यानी विभागाध्यक्षों द्वारा की जाने वाली भर्तियों में सेलरी कट का फार्मूला लगा दिया है। इसमें नई भर्ती वाले कर्मचारियों को पहले साल में 70 फीसदी, दूसरे साल में 80 फीसदी, तीसरे साल में 90 फीसदी और चौथे साल में 100 फीसदी यानी पूरा वेतन मिल पाएगा। इसमें प्रत्येक कर्मचारी को तीन साल में 2.50 लाख रुपए का नुकसान होगा, और पूरे सेवाकाल में 2019 में भर्ती हुए कर्मचारी की बराबरी नहीं कर पाएगा। प्रदेश में इस तरह का यह पहला मामला है जब अफसरों और कर्मचारियों की भर्ती में यह भेदभाव किया गया है। शेष पेज 8 पर

एक साल का अंतर पड़ेगा भारी

शासकीय सेवा में जो कर्मचारी 2019 में भर्ती हुए हैं उन्हें बराबर भर्ती की तारीख से शत प्रतिशत वेतन दिया जा रहा है और पहले साल से ही वेतनवृद्धि यानी हर साल 3 फीसदी का लाभ। वहीं, 2020 के बाद भर्ती में आने वाले कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तारीख के चौथे साल में यह लाभ मिल पाएगा। पहले के तीन सालों में जो भी नुकसान हुआ है, उसकी सेवाकाल में भरपाई नहीं होगी। इस तरह एक साल की भर्ती का अंतर कर्मचारियों पर भारी पड़ेगा।

आरजीपीवी: पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की तैयारी

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि (आरजीपीवी) पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन आइओटी और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल कोर्स शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के अधिकारियों समेत व पॉलिटेक्निक के प्राचार्यों से सुझाव भी लिए हैं। सुझावों के आधार पर आरजीपीवी दो डिप्लोमा कोर्स शुरू करगा। इसके साथ ही वह अन्य तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राज्य शासन को भेजा जाएगा। शासन की मंजूरी के बाद शुरुआत में इसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्तर के दो कोर्स के साथ लागू किया जाएगा।

यह होगा विशेष

मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम के तहत विद्यार्थी तकनीकी कोर्स में प्रवेश लेता है और एक साल पढ़ने के बाद छोड़ देता है तो उसे एक साल का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी तरह यदि दो साल की पढ़ाई कर लेता है तो उसे आईटीआई का प्रमाणपत्र मिलेगा और तीनों साल की पढ़ाई करता है तो उसे इंजीनियरिंग का डिप्लोमा दिया जाएगा। इसके लिए एक क्रेडिट बैंक होगा।

नवीन मान्यता के लिए 10 तक करें आवेदन

भोपाल। सीबीएसई, आइसीएसई एवं अन्य शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता पाने वाले निजी स्कूल सत्र 2021-22 की नवीन मान्यता को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने तारीख में 10 दिन की बढोत्तरी कर दी है। अब स्कूल 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर थी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक केके द्विवेदी ने आदेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश जारी किए हैं।

सत्र 2022-23 की मान्यता : सीबीएसईए आइसीएसई एवं अन्य बोर्ड के तहत मान्यता पाने वाले स्कूल शैक्षणिक सत्र 2022-23 की मान्यता, अपग्रेडेशन, नवीनीकरण एवं राज्य की एनओसी के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे।

आईआईटीटीएम में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा-

संस्कृत केवल भाषा नहीं, हमारी संस्कृति भी है

अब इसे सीखने भारत ज्यादा आते हैं विदेशी

संस्कृत कोर्स का शुभारंभ

सिटी रिपोर्टर . ग्वालियर

विदेशी दो भाषा को अच्छी तरह समझते हैं। इनमें एक अंग्रेजी और दूसरी संस्कृत है। अंग्रेजी वह बोलते हैं और संस्कृत के श्लोक उन्हें याद हैं, जबकि देश के युवा इस देववाणी को बोलने में संकोच करते हैं। संस्कृत केवल भाषा ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की परिचायक है। समस्त प्राचीनतम भाषाओं में संस्कृत का स्थान सर्वोच्च है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से इस भाषा को सीखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी छात्र भारत आते हैं।

यह बात केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कही। वह भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) में शुक्रवार को ऑनलाइन संस्कृत पाठ्यक्रम के शुभारंभ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व साहित्य की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद संस्कृत में ही रची गई है। संस्कृत से ही कई भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। इसे भारतीय भाषाओं की जननी माना गया है। अध्यक्षता सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जालिम सिंह, संस्थान के डायरेक्टर डॉ.आलोक शर्मा, डॉ.चंद्रशेखर बरूआ, डॉ. सौरभ दीक्षित सहित संस्थान के विद्यार्थी भी मौजूद रहे।

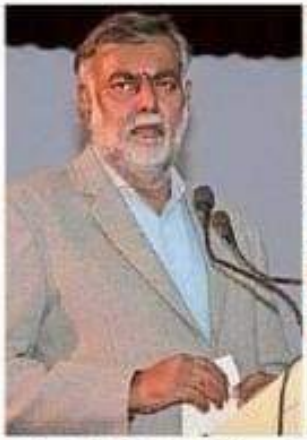

• संस्कृत कोर्स के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और मौजूद फैकल्टी।

• परिक्रमा पथ का शुभारंभ करते अतिथि।

1.2 किलोमीटर लंबा है परिक्रमा पथ

आईआईटीटीएम ग्वालियर परिसर में परिक्रमा पथ का भी शुभारंभ किया गया। 1.2 किलोमीटर लंबे इस पथ को संस्थान के चारो ओर बनाया गया है। इस पथ पर चलते हुए एक तरफ महलनुमा संस्थान का वास्तुशिल्प दिखाई देगा, जबकि दूसरी ओर हरियाली देखने को मिलेगी। इस पूरे परिक्रमा पथ में करीब 1500 हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं। कोविड-19 को देखते हुए फिलहाल संस्थान के विद्यार्थी और फैकल्टी इसे उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद इसे शहरवासियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। जिससे सुबह और शाम को शहरवासी यहां वॉक कर सकेंगे।

भूजल संवर्धन प्रणाली शुरू

संस्थान में भूजल संवर्धन प्रणाली का भी शुभारंभ हुआ। इससे परिसर की 10 हजार स्कवायर फीट एरिया का प्रतिवर्ष 9 लाख 10 हजार लीटर पानी का संरक्षण हो सकेगा। इस पानी को ट्रीटमेंट कर इसे पीने योग्य बनाया जाएगा। दूसरे चरण में 70 हजार स्कवायर एरिया के पानी को संरक्षण करने की योजना है।

विश्वविद्यालय की आपात कार्य परिषद बैठक 7 को

■ 1995 में नियमित हुए कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण का लाभ प्रमुख मसला, बढ़ सकता है विवाद

स्टार समाचार | रीवा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की आपात बैठक 7 दिसंबर को बुलाई गई है। इस बैठक के अनेक ऐसे बिंदु हैं जो विवादास्पद हैं बिंदु क्रमांक 2 में कर्मचारी संघ के पत्र के संदर्भ में वर्ष 95 में नियमित हुए कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण का लाभ दिए जाने का भी मुद्दा है। जबकि नियमित कर्मचारियों के लिए तो पहले से ही इसकी पात्रता है। इस संबंध में ज्ञात हुआ है कि कुलसचिव द्वारा वर्ष 2012 में दो नियमित वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने के उपरांत उन्हें अवकाश के नगदीकरण का भुगतान किए जाने के आदेश जारी कर दिए थे। जो अनियमित है और जिस पर राज्य शासन द्वारा जानकारी चाही गई थी। इस अनियमित भुगतान को कार्य परिषद से मंजूरी दिलाने के उद्देश्य से ही यह बैठक आयोजित की गई है। नियमानुसार अवकाश के नगदीकरण की पात्रता उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों को होती है जो विवि की नियमित सेवा में है। नियमित वेतनमान प्राप्त या दैनिक कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार अवकाश वेतन का भुगतान किया जाना अनियमितता की श्रेणी में आता है। यदि इसे कार्य परिषद द्वारा मंजूर किया गया तो विश्वविद्यालय के ऊपर पर लगभग 50 लाख रुपए के अतिरिक्त व्यय भार के आने की संभावना है। इस प्रकार किया गया भुगतान भी शासकीय राशि के दुरुपयोग का मुद्दा बनेगा।

पिछली 6 बैठकों का कार्य वृत्त भी होगा अनुमोदित

कार्यपरिषद की बैठक में विद्या परिषद की पिछले 8 माह की 6 बैठकों का कार्यवृत्त भी अनुमोदित कराया जा रहा है। यह पहली बार हो रहा है जब आपातकालीन बैठक में ऐसे मुद्दे चर्चा में हैं जो आपत्तिक प्रकृति के नहीं है। 1995 में नियमित हुए कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण का लाभ दिए जाने के मसले के अलावा आयुर्वेद विषय के पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी प्रकरण पर 23 मार्च 2020 को हुई कार्य परिषद की बैठक के अनुसार गठित समिति जो समस्त तथ्यों से अवगत हो चुकी है, उसके प्रतिवेदन पर विचार किया जाएगा। साथ ही विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक के कार्य वृत्त के अनुमोदन पर विचार किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर के पत्र क्रमांक खेयुक/अधो/420 दिनांक 28 नवंबर 2020 के संबंध में खेल युवा कल्याण विभाग के निर्माणाधीन जिला खेल परिसर के निर्माण में आ रही कठिनाइयों के निवारण के लिए 27 नवम्बर को आयोजित की गई बैठक में लिए गए फैसलों की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

कुलपति के आश्वासन के बाद भी जारी है गेस्ट फेकेल्टी का धरना

नई माह से मानदेय न मिल पाने के चलते विश्वविद्यालय के समस्त अतिथि विद्वान विगत तीन दिन से धरने पर हैं और आगे भी वेतन भुगतान न होने तक प्रदर्शन करने की मंशा बनाए हुए हैं। वित्त नियंत्रक की अनुपस्थिति के कारण यह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं कोई भी अधिकारी वित्त नियंत्रक का प्रभार नहीं संभालना चाहता। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रबंधन असहाय हो गया है। कुलपति प्रो. एनपी पाठक ने अतिथि विद्वानों को समझाइश देते हुए यह आश्वासन दिया है कि 7 दिसम्बर के बाद उनका भुगतान कर दिया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद भी अतिथि विद्वान अपने मांग और प्रदर्शन पर अडिग हैं और तब तक प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं जब तक उनका भुगतान नहीं हो जाता। जाहिर है कि पिछले 6 महीने से वेतन न मिल पाने के कारण अतिथि विद्वानों में खासी नाराजगी है। एक तरफ जहां सरकार शासकीय महाविद्यालय के अतिथि विद्वानों को प्रति माह वेतन दिए जाने का आदेश जारी करती है वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय में इतने लंबे वक्त से अतिथि विद्वानों का मानदेय रोककर रखा था। वहीं कुछ ऐसे भी आपत्तियां उठाई गई हैं कि जब लॉक डाउन के वक्त विश्वविद्यालय की कक्षाएं संचालित नहीं हुईं तो अतिथि विद्वानों को किस आधार पर मानदेय वितरित कर दिया जाए। वहीं अतिथि विद्वान यह कह रहे हैं कि जब सरकार ने शासकीय कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों का मानदेय जारी किया है तो विश्वविद्यालय को भी करना चाहिए।

बिना स्वैप किए ही कार्ड से होगा 5,000 रुपये तक भुगतान

नई दिल्ली, ब्यूरो : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए देश में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने वाले कुछ कदम उठाए हैं। लेकिन हाल के दिनों में कुछ बैंकों की डिजिटल सेवा नेटवर्क में समस्या आने पर चिंता भी जताई है। केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों को कहा है कि वह तकनीक में और ज्यादा निवेश करें ताकि सर्विस की गुणवत्ता सुधारी जा सके। आरबीआइ के गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने डिजिटल बैंकिंग से होने वाले भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ नई व्यवस्था करने की घोषणा की है। पिछले दिनों आरबीआइ ने निजी सेक्टर के एचडीएफसी बैंक को डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने से रोक दिया है।

दास ने एचडीएफसी बैंक की सेवाओं पर लगाई गई रोक के बारे में कहा कि उस बैंक में पहले भी ग्राहकों के साथ लगातार समस्या आ रही थी। जब देश में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा हो तब लाखों ग्राहकों को तकनीकी खामियों के भरोसे छोड़ा और डिजिटल बैंकिंग के प्रति लोगों का भरोसा तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि एसबीआइ की डिजिटल सेवा में जो दिक्कत आई है उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आरबीआइ ने एक अप्रत्याशित कदम के तहत इस सप्ताह गुरुवार को एचडीएफसी बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी है। वैसे, मौद्रिक नीति समीक्षा में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने वाले कई कदम हैं। जैसे अब कांटेक्टलेस कार्ड से भुगतान की 2,000 रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है। यह व्यवस्था अगले वर्ष पहली जनवरी से लागू होगी। इसके तहत चिप लगे डेबिट व क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपये तक का भुगतान करने के लिए उन्हें स्वैप नहीं करना पड़ेगा।

पिछड़ा वर्ग के 35 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन योजना में छात्रवृत्ति मंजूर

भोपाल। प्रदेश में इस वर्ष विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में उच्च अध्ययन के लिए 35 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि मंजूर की गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा योजना में इस वर्ष पिछड़ा वर्ग के 50 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया गया है। विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों के नवीनीकरण समेत इस वर्ष की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के रूप में करीब 9 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है। जिन विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के लिए राशि मंजूर की गई है, वे विद्यार्थी मुख्य रूप से कानून की पढ़ाई, मास्टर इन्फोर्मेशन ऑफ टेक्नालॉजी, मास्टर्स इन फाइनेंसियल एकाउंटिंग, मास्टर ऑफ एडवांस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमएस केमेस्ट्री, मास्टर्स लॉयजिसटिक्स एण्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमएससी इन्टरनेशनल फैशन मार्केटिंग, एमबीए इन्टरनेशनल बिजनेस आदि विषयों के लिए विदेश गए हैं। चयनित छात्र मुख्य रूप से आस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, अमेरिका, नीदरलैंड, आदि देशों के विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन के लिए गए हैं।

170 आयुर्वेद महाविद्यालयों की मान्यता खतरे में

भोपाल। मध्यप्रदेश के 19 आयुर्वेद कॉलेजों में से 6 राजस्थान के, 4 बिहार के, 4 उत्तरप्रदेश के, 5 आयुर्वेद कॉलेज समेत देशभर के 170 आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं! विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि देशभर के 400 से ज्यादा आयुर्वेद महाविद्यालयों में से जिन 170 कॉलेजों पर संकट है उनमें प्रमुख रूप से हायर फैकल्टी जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर की समस्या प्रमुख कारण है। कोरोनाकाल में मरीजों से संबंधित आईपीडी व ओपीडी की समस्या न के बराबर है। फिलहाल ऑल इण्डिया सेंट्रल कोटे की 15 फीसदी सीटों पर प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग जारी है। आज सीट आवंटन सूची जारी होगी और संबंधित कॉलेजों में 5 से 12 दिसंबर तक रिपोर्टिंग देना है! नीट से ही देशभर की 40 हजार से ज्यादा आयुष स्नातक सीटों पर प्रवेश होने हैं। आयुष मेडीकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राकेश पाण्डेय ने बताया कि आयुर्वेद कॉलेजों पर मान्यता संबंधित संकट के बादल होने के कारण स्टेट कोटे की काउंसलिंग में विलंब से सत्र लेट होने के आसार हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय शीघ्र ही मान्यताओं पर निर्णय करे तो बेहतर है।

सीबीआई ने किया परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में चालान पेश

भोपाल(आरएनएन)। व्यापमं की वर्ष 2012 में आयोजित की गई परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसबी साहू की अदालत में 18 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा- 466, 467,468,419,420 और 120 बी के अलावा मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 3/4 के तहत पूरक चालान पेश किया है। यह चालान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने पेश किया है। विशेष न्यायाधीश ने इस दौरान अदालत में अनुपस्थित रहने पर सभी 18 आरोपियों के खिलाफअरेस्ट वारंट जारी किया है। अरेस्ट वारंट जारी किए जाने की जानकारी मिलते ही पांच आरोपियों संजय अलोरिया,अनार सिंह, कैलाश कुमार निमोरिया, कोमल सिंह एवं संजय सोलंकी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पेश किए गए हैं। विशेष न्यायाधीश ने जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु 12 दिसंबर की तारीख तय की है। उल्लेखनीय है कि व्यापमं मामलों की जांच सबसे पहले एसटीएफ द्वारा की गई थी। एसटीएफने परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में पहले 52 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। एसटीएफने अपने चालान में पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और उनके ओएसडी रहे ओमप्रकाश शुक्ला सहित अन्य 7 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यापमं मामलों की जांच एसटीएफसे वापस लेकर सीबीआई के सुपुर्द की गई थी, सीबीआई ने मामले की जांच के बाद 19 जनवरी 2019 को अन्य 26 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था।

अदालत ने सभी 18 आरोपियों के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट

डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन का रिजल्ट जारी

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एज्युकेशन प्रथम वर्ष (प्रथम अवसर) एवं द्वितीय वर्ष (प्रथम अवसर) परीक्षा सितंबर वर्ष 2020 का रिजल्ट गुरूवार को जारी कर दिया है। इस प्रथम वर्ष (प्रथम अवसर) की परीक्षा में 42,469 एवं द्वितीय वर्ष (प्रथम अवसर) की परीक्षा में 34,908 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। प्रथम वर्ष (प्रथम अवसर) का परीक्षा परिणाम 47.07 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष (प्रथम अवसर) का परीक्षा परिणाम 80.28 प्रतिशत रहा है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट मंडल की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

दो दिन में हल करना होंगे प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं बीयू के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर जमा करना होगा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) ने स्नातक अंतिम वर्ष व स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एक और मौका दिया है। यह परीक्षाएं 8 दिसंबर से ओपन बुक पद्धति पर होंगी। विद्यार्थियों को दो दिन में प्रश्न पत्र हल करना होंगे और उत्तर पुस्तिकाएं बीयू के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर जमा करना होंगी।

विद्यार्थी अपने प्रवेश पत्र स्टूडेंट इंफार्मेशन सिस्टम (एसआइएस) से डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षार्थियों के लिए बीयू के टाइम टेबल के मुताबिक प्रश्नपत्र बीयू की वेबसाइट पर कक्षा और विषयवार लोड किए

Published in 05 Dec 2020 print edition of Raj Express

ऑनलाइन शिक्षा : दशा व दिशा विषय पर मंथन

भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों ने 4 दिसंबर को ऑनलाइन शिक्षाः दशा और दिशा विषय पर मंथन किया। कुलपति प्रो. केजी सुरेश ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण अध्ययन-अध्यापन ऑनलाइन मोड में है। ऑनलाइन शिक्षा का अधिकतम लाभ विद्यार्थियों को मिले, इसके लिए निरंतर मूल्यांकन और नवाचार आवश्यक है। कुलपति ने कहा कि जल्द ही शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग करने की प्रक्रिया पर ई-बुक प्रकाशित की जाएगी। कुलपति ने कहा कि हम जल्द ही विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय, अन्य संस्थाओं और प्राध्यापकों के सहयोग से ऑनलाइन कंटेंट की व्यवस्था भी बनाएंगे। बैठक में शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए। शिक्षकों ने बताया कि वे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, मूक, स्वयं, स्वयंप्रभा जैसे भारत सरकार के डिजिटल नवाचारों का उपयोग कर रहे हैं। शिक्षक ऑनलाइन क्लास के लिए गूगल मीट, गूगल क्लास रूम, गूगल वेबसाइट, गूगल फॉर्म, मूडल इत्यादि प्लेटफार्म का उपयोग कर रहे हैं। प्रैक्टिकल गतिविधियों में विद्यार्थियों को ऑनलाइन असाइनमेंट दिए जा रहे हैं।

विद्यार्थी परिषद का अभ्यास वर्ग सम्पन्न

भोपाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भोपाल महानगर इकाई ने गुरुवार को एक दिवसीय अभ्यास वर्ग कोटरा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में रखा। भोपाल गैस त्रासदी के दिन को याद करते हुए, परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिविर स्थल से भारत माता चौराहा तक साइकिल चलाकर प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, जिसके उपरांत भारत माता की प्रतिमा के समक्ष पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। शिविर में बैठक की रूपरेखा, निर्णय प्रक्रिया एवं परिषद की कार्य पद्धति समेत तीन विषयों पर सत्र संचालित हुए। इनमें विषय से संबंधित वक्ताओं ने उद्बोधन दिया। निर्णय प्रक्रिया पर उद्बोधन देते हुए विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतस सुखाड़िया ने कहा कि विद्यार्थी परिषद की कार्यशैली में कोई भी प्रस्ताव बहुमत से पारित नहीं होता, यहां सर्वानुमति होना बहुत आवश्यक होता है। परिषद का हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। महानगर संगठन मंत्री संदीप वैष्णव ने कहा कि एबीवीपी की सबसे प्राथमिक सीढ़ी कैंपस की इकाई है।

सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए अब 18 तक आवेदन

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने देश भर के सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिए होने वाले ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम (एआइएसएसईई-2021) आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। छठी और नौवीं क्लास में दाखिले के लिए अब 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। देशभर के 33 सैनिक स्कूलों में 2021-22 सत्र में दाखिले के लिए एनटीए लिखित परीक्षा आयोजित करती है। ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत और कोविड-19 को देखते हुए दूसरी बार आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है।

एमफिल, पीएचडी के छात्र जून तक जमा कर सकेंगे शोधपत्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोरोना के चलते एमफिल और पीएचडी के छात्रों को शोधपत्र जमा करने के लिए और छह माह का समय दिया है। अब अंतिम तिथि 30 जून कर दी गई है। हालांकि, फेलोशिप की अवधि पांच वर्ष तक ही रहेगी।

यूजीसी ने बढ़ाई थिसिस जमा करने की तारीख

भोपाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एमफिल) और डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) के अंतिम सत्र के लिए थीसिस जमा करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले थिसिस जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी। अब इसे 30 जून 2021 कर दिया गया है। इस संबंध में यूजीसी ने आधिकारिक बयान जारी किया है। यूजीसी ने सितंबर-अक्टूबर सत्र 2020-21 के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर कर दी है। (नरि)

स्नातक अंतिम वर्ष व स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी 8 से दे सकेंगे ओपन बुक पद्धति से परीक्षाएं

जाएंगे। 250 शब्द में प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। सुबह सभी विषयों के पेपर लोड किए जाएंगे। इसके बाद विद्यार्थी इन्हें डाउनलोड कर घर पर ही उत्तर लिखेंगे। बीयू के अधिकारियों के मुताबिक परीक्षार्थी केवल नीले या काले रंग के बालपेन का प्रयोग करेंगे। यह विशेष अवसर परीक्षा है। इसके बाद छूटे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा नहीं होगी। बता दें कि कोरोना के संक्रमण के कारण बीयू में इस साल पहली बार ओपन बुक पैटर्न पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। राज्य शासन और यूजीसी की गाइडलाइन के आधार पर बीयू ने सितंबर में परीक्षा आयोजित की थी। लेकिन इसके साथ ही स्पष्ट कर दिया था कि जो विद्यार्थी किसी वजह से इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी वजह से यह परीक्षा आयोजित की जा रही है।

डाक व्यवस्था भी होगी

यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही हैं, जो इसके पहले आयोजित हुई परीक्षाओं में किसी वजह से शामिल नहीं हो सके थे। परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा। जो विद्यार्थी बीयू के संग्रहण केंद्र में उत्तर पुस्तिका जमा नहीं कर पा रहे, उन्हें उपकुलसचिव (गोपनीय शाखा) बरकतउल्ला विवि, भोपाल के पते पर 15 दिसंबर तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजना होगी।

तकनीकी शिक्षाः बीई में 22 हजार 28 सीट खाली, आज एडमिशन का अंतिम दिन

भास्कर न्यूज . भोपाल | तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा बीई, फार्मेसी, एमबीए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सहित अन्य सभी तकनीकी कोर्सेस के लिए शुरू की गई एडमिशन प्रक्रिया के तहत शुक्रवार से अंतिम राउंड की कॉलेज लेवल काउंसलिंग शुरू हुई।

बीई में एडमिशन की प्रकिया 22 सितंबर से शुरू की गई थी। कोरोना संक्रमण के देशभर में बन रही अलग-अलग स्थिति के कारण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा एकेडमिक कैलेंडर को 6 बार से ज्यादा बदला। आखिरी फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए अंतिम तारीख 5 दिसम्बर तय की है। इसलिए मप्र तकनीकी शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं के लिए सीएलसी आयोजित कराकर एडमिशन लेने का अवसर दिया है। शुक्रवार को बीई में करीब एक हजार छात्र-छात्राओं ने एडमिशन ले लिया है। वहीं शाम 5 बजे तक 30 हजार 54 एडमिशन हो चुके थे। बीई सहित अन्य पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने के लिए शनिवार अंतिम दिन है।बीई में अभी 22 हजार 28 सीट खाली हैं इन पर एडमिशन के लिए 3 दिसम्बर तक रजिस्ट्रेशन करा चुके विद्यार्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एमबीए में 22 हजार 115 एडमिशन, बी. और डी. फार्मेसी में 16 हजार 664 एडमिशन हुए हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 14 हजार 544 एडमिशन हुए हैं।

अब 19 दिसंबर तक कॉलेजों में जमा हो सकेंगे दस्तावेज

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए दस्तावेज कॉलेज में जमा करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अब 19 दिसंबर तक कॉलेज में ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) व माइग्रेशन जमा कर सकते हैं। पूर्व में इन दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तारीख 12 दिसंबर थी। -नप्र

पॉलिटेक्निक के दो नए डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगा आरजीपीवी

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) प्रस्ताव तैयार कर रहा है। आरजीपीवी ने इस संदर्भ में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के अधिकारियों व पॉलिटेक्निक के प्राचार्यों से सुझाव भी लिए हैं। इन्हीं सुझावों के आधार पर आरजीपीवी दो डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की तैयारी भी कर रहा है। इसके साथ ही वह अन्य तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राज्य शासन को भेजा जाएगा। शासन की मंजूरी के बाद शुरुआत में इसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्तर के दो कोर्स के साथ लागू किया जाएगा। इसके बाद यह स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों में लागू होगा। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट सिस्टम के तहत विद्यार्थी तकनीकी कोर्स में प्रवेश लेता है और एक साल पढ़ने के बाद छोड़ देता है तो उसे एक साल का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी तरह यदि दो साल की पढ़ाई कर लेता है तो उसे आइटीआइ का प्रमाणपत्र मिलेगा और तीनों साल की पढ़ाई करता है तो उसे इंजीनियरिंग का डिप्लोमा दिया जाएगा। इसके लिए एक क्रेडिट बैंक होगा। यदि दो साल की पढ़ाई करने के कुछ साल बाद वह दोबारा से डिप्लोमा पूरा करना चाहता है तो विद्यार्थी को एक साल की शेष पढ़ाई करनी होगी। वहीं क्रेडिट बैंक की सहायता से पूर्व में की गई दो साल की पढ़ाई के क्रेडिट जाएंगे। इस तरह तीन साल का डिप्लोमा पूरा हो जाएगा।

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह कोर्स होंगे शुरू

आरजीपीवी के कुलपति प्रो. सुनील कुमार ने बताया कि पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन आइओटी और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल कोर्स शुरू किए जाएंगे। सत्र 2021-22 से भोपाल के दोनों शासकीय पॉलिटेक्निक में संचालित करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाएगा।

दो दिन में हल करना होगा प्रश्न पत्र, केंद्र पर जमा होंगी उत्तर पुस्तिकाएं

बीयू में विशेष परीक्षा आठ दिसंबर से होगी शुरू

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष व स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आठ दिसंबर से होंगी। इसके प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को दो दिन में हल करने होंगे। इसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं को बीयू द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर जमा करना होगा। परीक्षा ओपन बुक पद्धति से उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही हैं, जो पहले परीक्षाओं में किसी वजह से शामिल नहीं हो सके थे। परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के लिए दो दिन का समय दिया जाएगा। जो विद्यार्थी बीयू के संग्रहण केंद्र में उत्तर पुस्तिका जमा नहीं कर पाएंगे, उन्हें उपकुलसचिव (गोपनीय शाखा) बरकतउल्ला विवि भोपाल के पते पर 15 दिसंबर तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजनी होगी।

सितंबर में हुई ओपन बुक पैटर्न परीक्षा में जो छात्र शामिल नहीं हो सके थे, उनकी परीक्षा आठ दिसंबर से शुरू होगी। परीक्षा से वंचित विद्यार्थी अपने प्रवेश पत्र स्टूडेंट इंफार्मेशन सिस्टम (एसआइएस) से डाउनलोड कर सकेंगे। यह विशेष अवसर परीक्षा है। इसके बाद छूटे विद्यार्थियों के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। परीक्षार्थियों के लिए बीयू के टाइम टेबल के मुताबिक प्रश्नपत्र बीयू की वेबसाइट www.bubhopal.ac.in पर कक्षा और विषयवार लोड किए जाएंगे। परीक्षार्थियों को 250 शब्द में प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। सुबह सभी विषयों के पेपर लोड किए जाएंगे। इसके बाद विद्यार्थी इन्हें डाउनलोड कर घर पर ही उत्तर लिखेंगे। बीयू के अधिकारियों के मुताबिक परीक्षार्थी केवल नीले या काले रंग के बालपेन का प्रयोग करेंगे।

अब 19 तक कॉलेजों में जमा हो सकेंगे दस्तावेज : उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए दस्तावेज कॉलेज में जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है। विद्यार्थी अब 19 दिसंबर तक ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) व माइग्रेशन जमा कर सकते हैं। पूर्व में इन दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तारीख 12 दिसंबर थी। तय समय-सीमा में अपने कॉलेज जाकर टीसी, माइग्रेशन जमा नहीं करने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को एमएलबी कॉलेज में फार्म जमा करने के लिए लगी युवतियों की लाइन। ● नवदुनिया

ऑनलाइन ई-एडमिशन के लिए दस्तावेज जमा करने की तिथि बढ़ी

भोपाल। महाविद्यालय में ऑनलाइन ई-प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए दस्तावेज जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। सत्र 2020-21 सीएलसी पांचवें चरण में जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट हुए हैं, वे टीसी, माइग्रेशन एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराकर 12 दिसंबर तक कॉलेजों में जमा करा सकते हैं। पहले दस्तावेज जमा कराने की तिथि 24 नवंबर थी। यह जानकारी महाविद्यालय, भोपाल के प्राचार्य द्वारा सभी शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं निजी अशासकीय कॉलेज के प्राचार्यों को पत्र के माध्यम से दी गई है।

व्यवस्था

प्रतियोगी परीक्षाओं में मॉक टेस्ट कर रहे मदद

पीईबी की वेबसाइट पर विद्यार्थी समझ सकते हैं परीक्षा की प्रक्रिया

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) की एक सुविधा से हजारों विद्यार्थियों को प्रतियोगी और भर्ती परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल रही है। पीईबी की वेबसाइट http://peb.mp.gov.in/ पर मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। यहां से विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा देने के पहले ट्रायल के तौर पर टेस्ट दे सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तो जानने को मिल ही रही है यह भी पता लग रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पीईबी की इस सुविधा का उपयोग अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी कर रहे हैं। पीईबी द्वारा मॉक टेस्ट के लिए अपने सर्वर में हजारों प्रश्नों को जोड़ा गया है। इससे विद्यार्थी जैसे ही एक प्रश्न का जवाब देता है, नया प्रश्न आ जाता है। विद्यार्थी मॉक टेस्ट देते समय पिछले और अगले प्रश्नों को देख भी सकते हैं। जिन प्रश्नों के जवाब नहीं बनते हैं उन्हें विद्यार्थी बुकमार्क भी कर सकते हैं ताकि बाद में उसका अध्ययन कर सकें।

नए वर्ष में ये परीक्षाएं होंगी

पीईबी जनवरी 2021 में सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, डेटा इंट्री ऑपरेटर पदों के लिए परीक्षा लेगा। फरवरी 2021 में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। पुलिस मुख्यालय की आरक्षक संवर्ग की भर्ती परीक्षा मार्च 2021 में कराई जाएगी।

विशेषज्ञ रोजाना मॉक टेस्ट देने की सलाह देते हैं

परीक्षा विशेषज्ञ ओपी तिवारी का कहना है अब ज्यादातर परीक्षाएं ऑनलाइन होने लगी है। कई विद्यार्थी पहली बार ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे है। ऐसे में उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रश्न किस तरह मॉनिटर पर दिखाई देते है और उन्हें किस तरह प्रश्नों के जवाब पर क्लिक करना होता है। इन सभी बातों का ध्यान रख कर विद्यार्थी निर्धारित समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के जवाब दे सकते है। इससे यह भी पता लगता है कि ऑनलाइन परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते है।

सीबीआई ने परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाले में 18 आरक्षकों को दोषी माना

परीक्षा में इनके स्थान पर बैठे थे मुन्नाभाई, कोर्ट में चार्जशीट पेश

पीपुल्स ब्यूरो ● भोपाल

2012 में हुई परिवहन आरक्षक भर्ती में सीबीआई ने 18 ऐसे आरक्षकों को चिह्नित कर लिया है, जिनके नाम पर दूसरे लोगों ने (इम्परसोनेट) परीक्षा दी थी। गिरफ्तारी के लिए इन सभी के नाम पर वारंट निकाले जा रहे हैं।

सीबीआई ने शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट में इस मामले की दूसरी चार्जशीट पेश कर दी। 5 साल तक चली छानबीन में सीबीआई ने 'मुन्नाभाइयों' की तलाश में यूपी के कई शहरों में छापेमारी की। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि मामले में उनका फोकस ऐसे लोगों को चिह्नित करने पर था, जिनके स्थान पर दूसरे लोगों ने परीक्षा दी थी। सीबीआई ने ऐसे 20 मामले निकाले जिनमें 19 आवेदकों के दस्तावेजों का मिलान नहीं हुआ।

ये हैं 18 आरक्षक : विनोद टैगोर, बालाजी गुर्जर, मनीष सालविया, कोमल सिंह, राजेश कुमरे, अरविंद कुमरे, कुलदीप सिंह, चंद्रभूषण गौतम, मुकेश कुमार, अनार सिह, संजय सोलंकी, शिवमंगल सिंह सुमन, शैलेंद्र कुमार माझी, राजेश अलोरिया, संतोष सिह नरवरिया, रामलखन सिंह गुर्जर, कैलाश कुमार निमोरिया एवं राहुल पाठक। राहुल पाठक पहले 'डिसमिस' हो चुका है। 17 नौकरी कर रहे हैं।

ओपन बुक एग्जाम में भी आधे स्टूडेंट्स फेल, ऐसे छात्रों को एक और मौका देगा बीयू

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

बीयू के बीएससी, बीए एवं बीकॉम के फाइनल ईयर के एग्जाम में 83 हजार स्टूडेंट्स में से लगभग आधे स्टूडेंट फेल हो गए हैं। बताया जाता है कि कई छात्रों का फर्स्ट-सेकंड ईयर में बैक लगने और एटीकेटी के एग्जाम नहीं होने के कारण उनके नंबर इंटरनल असेसमेंट में नहीं जुड़ सके हैं। इसके चलते अधिकांश छात्रों का रिजल्ट खराब हो गया है। हालांकि जो छात्र ओपन बुक एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें बीयू द्वारा परीक्षा का एक और मौका दिया जा रहा है।

कोरोना संक्रमण के कारण बीयू में फाइनल ईयर के एग्जाम ओपन बुक पद्धति से आयोजित किए गए थे। इसमें ओपन बुक के 50 प्रतिशत व इंटरनल असेसमेंट के 50 प्रतिशत अंक मिलाकर रिजल्ट तैयार होना था। प्रायः सभी छात्र ओपन बुक में तो पास हो गए हैं, लेकिन उनके कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट के नंबर नहीं मिले इस वजह से उन्हें फेल कर दिया गया है। रिजल्ट देखने के बाद छात्र-छात्राएं तनाव में हैं। कई छात्र-छात्राएं यूनिवर्सिटी भी पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें बताया जा रहा है कि कॉलेज से नंबर न मिलने के कारण ऐसा हुआ है। इस संबंध में कॉलेज प्राचार्यों से संपर्क किया जा रहा है। कॉलेज से विद्यार्थियों के नंबर आते हैं, तो रिजल्ट सुधारकर जारी किए जाएंगे।

ओपन बुक एग्जाम 8 से, दो दिन में हल करना होगा प्रश्न-पत्र

बीयू ने यूजी फाइनल ईयर व पीजी अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एक और मौका दिया है। परीक्षाएं 8 दिसंबर से ओपन बुक पद्धति पर होंगी। विद्यार्थियों को दो दिन में प्रश्न-पत्र हल करना होंगे और उत्तर पुस्तिकाएं बीयू के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर जमा करनी होंगी। विद्यार्थी प्रवेश पत्र स्टूडेंट इंफार्मेशन सिस्टम (एसआइएस) से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रश्नपत्र बीयू की वेबसाइट पर कक्षा और विषयवार लोड किए जाएंगे। 250 शब्द में प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। सुबह सभी विषयों के पेपर लोड किए जाएंगे। विद्यार्थी इन्हें डाउनलोड कर घर पर ही उत्तर लिखेंगे।

हम एक मौका दे रहे हैं

ओपन बुक एग्जाम के नंबरों के साथ इंटरनल असेसमेंट के नंबर होना जरूरी है। जिनका पिछले ईयर या सेमेस्टर में बैक लगा है, वह छात्र फेल हुए हैं। फिर भी हम उन्हें एक मौका और दे रहे हैं।

अजीत कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार, बीयू

सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड की नई मान्यता के लिए आवेदन 10 तक

भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय ने सीबीएसई, आइसीएसई एवं अन्य शिक्षा बोर्ड के

आदेश

निजी स्कूल सत्र 2021-22 की नवीन मान्यता के लिए अब 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर थी। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक केके द्विवेदी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं शैक्षणिक सत्र 2022-23 की मान्यता, अपग्रेडेशन, नवीनीकरण एवं राज्य की एनओसी के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसकी समय सारणी जारी की गई है।

भोपाल फ्रंट पेज

भोपाल, शनिवार, 05 दिसंबर, 2020

अभी मास्क ही वैक्सीन हैं

संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को भी 287 कोरोना मरीज मिले हैं। पिछले 10 दिनों से यह आंकड़ा 300 के आसपास है। ऐसे में फिलहाल मास्क ही वैक्सीन है। पुलिस कंट्रोल रूम के पास कुछ इस तरह मास्क को बेचे जा रहे हैं।

दो टीमें...और कार्रवाई

08 टीमें जिला प्रशासन की एसडीएम के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कर रही कार्रवाई, वहीं 19 टीमें नगर निगम की

03 लाख से अधिक का चालान रोज काट रही दोनों टीमें। ये टीमें करीब 600 चालान बनाती हैं। इसमें से कुछ डिस्टेंसिंग का पालन न करने के भी हैं।

1150 से अधिक लोगों पर पिछले 10 दिनों में नगर निगम ने कार्रवाई की मास्क न पहनने के मामले में, सबसे ज्यादा लोग बाजारों में बिना मास्क के मिले

100-500 रुपए तक का चालान एक व्यक्ति पर, लेकिन दुकान और बड़े स्टोर पर कोई बिना मास्क के मिला तो चालान 5000 रुपए या अधिक।

बढ़ता संक्रमण घटते इंतजाम...

3075 एक्टिव मरीज, 1600 से ज्यादा होम आइसोलेशन में लेकिन सैनिटाइजेशन स्प्रेयर 150 से घटकर 70 ही रह गए

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

शहर में फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लेकिन इससे बचने के इंतजाम घटते जा रहे हैं। यह हालात तब हैं जब शहर में कोरोना के 3075 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 1600 से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में है। लेकिन इन मरीजों के घर और उसके आसपास भी सैनिटाइजेशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि घरों में सैनिटाइजेशन के लिए उपयोग होने वाले स्प्रेयर खराब हैं। निगम के पास लगभग 150 स्प्रेयर हैं। इनमें से करीब 70 खराब है। आश्चर्य की बात यह है कि इन्हें रिपेयर करने का कोई इंतजाम भी निगम के पास नहीं है। नगर निगम ने अपने सभी 19 जोन के एएचओ को सैनिटाइजेशन के लिए स्प्रेयर दे रखे हैं। अलग-अलग तरह के स्प्रेयर मिला लिए जाएं तो लगभग 150 स्प्रेयर निगम के पास हैं। इनमें से कुछ इन एएचओ के पास दो से चार लोगों की टीम है जो घरों में सैनिटाइजेशन का काम करते हैं। लेकिन अभी कई इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम पूरी तरह बंद है।

निगम के एएचओ की दलील... इन मशीनों की रिपेयरिंग की अभी कोई व्यवस्था नहीं

स्प्रेयर की कमी के चलते अभी कुछ इलाकों में ही सैनिटाइजेशन हो पा रहा है।

फील्ड में पता चलता है मशीन खराब है

सैनिटाइजेशन का काम कर रहे ऑपरेटर बताते हैं कि फील्ड में जाने के बाद कई बार मशीन चालू ही नहीं होती। शुरुआत में एक दिन में 10 से 12 घंटे काम करने वाली इन मशीनों से बमुश्किल तीन-चार घरों में ही सैनिटाइजेशन हो पाता है। कई बार बीच में मशीन खराब हो जाने से लोग नाराज होते हैं उन्हें लगता है कि हम जानबूझकर सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं।

ज्यादातर के वॉल्व खराब हैं

नगर निगम के एएचओ बताते हैं कि इन मशीनों की रिपेयरिंग की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। सभी एएचओ अपने स्तर पर मशीन को रिपेयर कराते रहते हैं। अपने अनुभव से यह एएचओ बताते हैं कि कैमिकल का ज्यादा उपयोग होने से ज्यादातर के वॉल्व खराब हो रहे हैं। अब इन वॉल्व को बदलना जरूरी है।

सड़कों और गलियों में सैनिटाइजेशन का काम पूरी तरह बंद

सड़कों और गलियों के सैनिटाइजेशन का काम नगर निगम ने पूरी तरह बंद कर दिया है। कंटेनमेंट एरिया बनाने पर निगम उस एरिया में सड़कों और गलियों पर सैनिटाइजेशन करता था, इससे संक्रमण का खतरा भी कम होता था सके लिए अलग-अलग तरह की 24 मशीनें नगर निगम के पास हैं। इनमें से 4 मशीनें पिछले सप्ताह ही भोपाल आई हैं। लेकिन फिलहाल इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं हो रहा है।

नगर निगम को सोडियम हाइपो केमिकल मिल रहा फ्री

खास बात यह है कि सेनेटाइजेशन के लिए नगर निगम को सोडियम हाइपो क्लोराइड केमिकल फ्री में मिल रहा है। केवल उसका परिवहन का खर्चा देना होता है। वरिष्ठ अफसरों के अनुसार केमिकल की कोई कमी नहीं है। मशीनें उपलब्ध हैं, इसलिए सैनिटाइजेशन पर खर्चा बहुत कम है।

वर्कशॉप में इंतजाम करेंगे

स्प्रेयर की रिपेयरिंग के लिए वर्कशॉप में इंतजाम करेंगे। सभी एएचओ से रिपोर्ट बुलवा रहे हैं कि कितने स्प्रेयर में क्या खराबी है। गलियों और सड़कों पर सैनिटाइजेशन की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि कोरोना वातावरण से नहीं मनुष्य के संपर्क से फैल रहा है।

- वीएस चौधरी कोलसानी, कमिश्नर, नगर निगम

संक्रमण की रफ्तार

भोपाल में कोरोना के 287 नए मामले, एक की मौत

राजधानी में पिछले कई दिनों से पॉजिटिव मरीजों की आंकड़ा 250 से ऊपर बना हुआ है। शुक्रवार को भी शहर में 287 नए संक्रमित मिले। एक मरीज की मौत भी हुई। लगातार संक्रमित बढ़ने से एक्टिव केस भी 3075 हो गए हैं। इधर, प्रदेश में शुक्रवार को 1324 संक्रमित निकले और 14 मौतें भी हुईं। अब प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या भी 2 लाख 11 हजार 698 हो गई है। शुक्रवार को प्रदेश के 32 जिलों में दस से भी संक्रमित बढ़े। इधर, अब कुल एक्टिव केस की संख्या 13,641 हो गई है।

प्रदेश में पहली से आठवीं तक के स्कूल इस सत्र में नहीं खुलेंगे

वड़ी राहत : सीएम ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण इस शैक्षणिक सत्र में अब पहली से आठवीं तक के स्कूल नहीं लगेंगे। अब इनकी कक्षाएं एक अप्रैल 2021 से ही शुरू होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 के चलते प्रदेश में पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। आगामी शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा। परीक्षा के बजाय पहली से आठवीं तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। इनकी कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होंगी। कक्षाओं में सुरक्षित शारीरिक दूरी और अन्य सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा। नवमीं एवं ग्यारहवीं के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक या दो दिन स्कूल बुलाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में हर सरकारी स्कूल को श्रेष्ठ बनाना है, इसके लिए प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए शिक्षाविदों की एक समिति बनाई जाए। देश के अन्य राज्यों की शिक्षा पद्धति का अध्ययन कर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति लागू की जाए।

31 मार्च तक बंद रहेंगी पहली से आठवीं तक की कक्षाएं

परीक्षा के बजाय प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर होगा मूल्यांकन

1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा नया शिक्षा सत्र

9वीं, 11वीं के बच्चों को हफ्ते में एक दिन स्कूल बुलाया जाएगा

10वीं-12वीं बोर्ड की कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होंगी, परीक्षा भी ली जाएगी

निजी स्कूल सिर्फ शिक्षण शुल्क लें

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहेहैं, वे उस अवधि के लिए शिक्षण शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्क न लें। इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही हर शासकीय विद्यालय में नियमित पालक-शिक्षक संघ की बैठकें की जाएं।

10 हजार स्कूलों के लिए योजना

सीएम ने कहा, अगले तीन वर्षों में प्रदेश में खोले जाने वाले 10 हजार उच्च गुणवत्तायुक्त स्कूलों के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाईजाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जो अतिथि शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हें उसी विद्यालय में रखा जाए।

आवेदकों के लिए कुर्सी-पानी नहीं होने पर अधिकारियों को फटकारा

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली में कसावट लाने में जुटे कलेक्टर मनीष सिंह ने शुक्रवार को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) और पंजीयन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। पंजीयन कार्यालय में लोगों के बैठने का कोई प्रबंध नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। टीएंडसीपी कार्यालय में जनता से सीधे संवाद करने वाले लिपिकों से कहा कि आवेदकों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए।

कलेक्टर सिंह ने शॉपिंग कॉम्पलेक्स स्थित उप पंजीयन कार्यालय में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कई आवेदकों ने उन्हें शिकायत भी दर्ज करवाई। यहां आवेदकों के बैठने और पीने के पानी का प्रबंध नहीं था। सिंह ने पंजीयक प्रशांत पाराशर को इस बारे में फटकार भी लगाई। उन्होंने उनसे कहा कि आपने यहां बैठने तक का प्रबंध तक नहीं किया है। पानी की व्यवस्था भी नहीं है। बुजुर्ग आवेदकों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर पाराशर ने कोविड-19 का हवाला

औचक निरीक्षण

- **टीएंडसीपी और पंजीयक कार्यालय पहुंचे कलेक्टर**
- **लिपिकों से बोले- जनता को नहीं आए कोई समस्या**

देते हुए बताया कि महामारी के चलते कुर्सियां हटा दी गई हैं। इस पर कलेक्टर ने कहा कि आप शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए बैठक व्यवस्था बना सकते हैं। कलेक्टर टीएंडसीपी कार्यालय भी पहुंचे। उन्होंने संयुक्त संचालक के साथ कार्यालय के सभी लिपिकों को सख्त निर्देश दिए कि वे आमजन के कार्यों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि दलालों का एक भी काम नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने कार्यालय में कार्यों की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने वाले फ्लेक्स लगाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने आवेदकों से सीधे संपर्क में आने वाले पांच लिपिकों से चर्चा की। उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया कि आमजन के कामों को प्राथमिकता दें। दलालों के एकभी काम नहीं होने चाहिए।

ओपन बुक पद्धति से आइईटी के छात्र घर बैठे देंगे परीक्षा

विभिन्न कोर्स के करीब दो हजार विद्यार्थी

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमण बढ़ने से शैक्षणिक संस्थान खोलने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आइईटी) अपने विद्यार्थियों की इंटरनल एग्जाम करवाने जा रहा है। यह परीक्षा भी ओपन बुक पद्धति से होगी। घर बैठे विद्यार्थी यह इंटरनल एग्जाम दे सकेंगे।

संक्रमण के बीच यूजी फाइनल ईयर और पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा करवाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने ओपन बुक परीक्षा का सहारा लिया था। अब इसी फॉर्मूले को विश्वविद्यालय के कुछ अन्य विभागों ने अपना लिया है। वे इसके जरिए अपनी इंटरनल एग्जाम करवाने पर जोर दे रहे हैं। सत्र 2020-21 को लेकर आइईटी में सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो चुकी है।

पहले इंटरनल एग्जाम की तारीख तय हो गई है। विभाग ने प्रत्येक ब्रांच में ओपन बुक से परीक्षा करवाने की तैयारियां शुरू कर दी है। लगभग डेढ़ से दो हजार छात्र परीक्षा देंगे।

डायरेक्टर डॉ. संजीव टोकेकर ने बताया एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक विभाग में सत्र चल रहा है। पहली इंटरनल एग्जाम ओपन बुक से करवाएंगे। प्रत्येक विषय के प्रोफेसर ने पेपर बनाए हैं। वाट्सएप पर पेपर भेजकर विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिका बुलवाएंगे।

केंद्र सरकार ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

ऑनलाइन गेमिंग विज्ञापन में 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति बैन

नई दिल्ली| टीवी पर आ रहे ऑनलाइन गेमिंग व फैंटेसी स्पोर्ट्स के विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक ऐसे विज्ञापनों में अब 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिखाया जा सकता। इन विज्ञापनों के बाबत आ रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय के पास शिकायतें थीं कि गेमिंग के विज्ञापन उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं। इसके बाद मंत्रालय ने संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया को दिशा-निर्देश बनाने का जिम्मा सौंपा। ये 15 दिसंबर से प्रभावी होंगे।

डिस्क्लेमर अनिवार्य

- विज्ञापन के साथ यह डिस्क्लेमर अनिवार्य होगा कि ऑनलाइन गेमिंग में वित्तीय जोखिम है। इससे लत लगने का खतरा भी है।
- विज्ञापन प्रिंट मीडिया में है तो यह पूरे विज्ञापन का कम से कम 20 फीसदी हिस्सा होना चाहिए।
- ऑडियो-विजुअल मीडियम के विज्ञापन में यह डिसक्लेमर सामान्य गति से ही बोलते हुए सुनाई देना चाहिए।

विवि में 2578 पंजीयन हुए, कल त्रुटि सुधार का विकल्प

सागर| विवि में दाखिले के लिए पहले चरण की काउंसिलिंग जारी है। दो दिन में 2578 विद्यार्थी अपना पंजीयन करा चुके हैं। पंजीयन 6 दिसंबर की रात 11.30 बजे तक चालू रहेंगे। इस बीच कई विद्यार्थियों ने यह मांग भी की है कि जो फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनमें सुधार करने का विकल्प भी मिले। इसके पीछे विद्यार्थियों ने वजह बताई है कि ऑनलाइन फीडिंग करते समय कुछ जानकारी गलत भर दी गई हैं। ऐसे में एडमिशन सेल ने निर्णय लिया है कि विद्यार्थियों के लिए 6 दिसंबर को कुछ घंटों का समय भरे गए फॉर्म में सुधार करने के लिए मिलेगा।

आज का इतिहास

1950 अरबिंदो घोष - भारतीय लेखक का निधन हुआ।

1951 अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, प्रख्यात कलाकार तथा साहित्यकार का निधन हुआ।

1946 भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई।

1971 भारत ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी।

1997 भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, इटली में पोम्पेली और हम्रयूलेनियम स्थल, पाकिस्तान में शेरशाह सूरी निर्मित रोहतास का किला और बांग्लादेश में सुंदरवन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया।

अब बिना बाउंड्री वाले स्कूलों को नहीं मिलेगी मान्यता

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की मान्यता के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब निजी स्कूल संचालक फर्जी प्ले ग्राउंड दिखाकर स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। नया स्कूल खोलने के लिए स्कूल संचालकों को अब स्कूल में परिसर में खेल मैदान सहित अन्य सुविधाएं देना होंगी। शाला परिसर में पक्की और पर्याप्त ऊंचाई की बाउंड्री न होने पर भी मान्यता रोकी जा सकती है।

हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। स्कूल संचालक यदि इस अवधि में आवेदन नहीं करते हैं तो उन्हें 20 हजार रुपए लेटफीस के रूप में चुकाना होंगे। यह आवेदन सन् 2022-23 के लिए कराए जा रहे हैं। प्रदेश में फैले करोना वायरस के कारण इस साल शासन ने स्कूलों की मान्यता एक साल आगे बढ़ा दी थी। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक केके द्विवेदी ने सभी संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों, संस्था के अध्यक्षों, सचिवों व प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 के नियम में संशोधन करते हुए पुराने स्कूलों को मान्यता नवीनीकारण के लिए राहत देते हुए एक एकड़ भूमि की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। इन स्कूलों को 5600 वर्ग फीट और कक्षा 10वीं की मान्यता के लिए 4000 वर्गफीट तक जमीन को ही मान्य किया है, हालांकि कक्षा एक से बारहवीं तक का स्कूल एक ही परिसर में संचालित करने के लिए एक एकड़ भूमि होना भी अनिवार्य है।

खेल मैदान सहित अन्य सुविधा एक ही परिसर में जरूरी, आवेदन 15 तक

इस नियम के दायरे में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के तहत आने वाले सभी प्राइवेट स्कूल शामिल होंगे। अधिकारियों की मानें तो शासन की मंशा है कि प्रदेश में भले ही कम स्कूल खुलें, लेकिन जो भी खुलें, वो अच्छे हों। नए नियमों के तहत अब वे ही सोसायटी स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन करेंगी, जिनके पास पर्याप्त जमीन व राशि होगी।

बोर्ड कक्षाओं में प्रवेश के लिए अनुमति अनिवार्य : नए नियमों के तहत निजी स्कूल संचालकों को 10वीं एवं 12वीं कक्षा में 10 फीसदी से अधिक प्रवेश के लिए जिला शिक्षा अधिकारी एवं 20 फीसदी से अधिक प्रवेश के लिए लोक शिक्षण संचालनालय की अनुमति लेना होगी।